THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z.R. ANSARI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) About 0.505 million ha. of forest land has been lost for Irrigation and Hydel Projects in the country during the period 1951-52 to 1983-84-

Use of Foreign Brand Names in Television Manufacture

543. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Television Manufacturers Association appealed to the Prime Minister not to allow use of foreign brand names in low technology areas to enable the country to build up its own technological strength on the pattern of Japan and Korea ; and

(b) if so, what arc the details of the representation and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI SHIVRAJ PATIL) : (a) Yes. Sir.

(b) Indian TV Manufacturers Association (ITMA) in their representation have given the details of various factors which, *inter-alia,* refers to production, installed capacity, demand and pricing structure. While giving the above, they have made the following points :—

(i) It is their considered opinion that our country does not need the foreign brand name or the help of any multinational company to produce this low technology item, and

(ii) It has to be decided, whether the country of our size should have 2 or 3 large manufacturing facilities which obviously will be located in 2-3 towns of the country or we should have 2 or 3 good viable manufacturing units in each state and the union territory of the country.

As per the CTV and Black & White TV Policies, no foreign brand name would be allowed in the manufacture and sale of TV sets. AII such question of taking action does not arise.

Corruption charges against Haryana Chief Minister

544. DR. BAPU KALDATE : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Justice Jaswant Singh enquiring into the corruption charges against Haryana Chief Minister levelled by major opposition parties has completed his enquiry ;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what follow-up action has been taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) Yes, Sir.

(b) Shri Justice Jaswant Singh, in his report submitted to the Government, has concluded that there is no *prima facie* case against .Shri Bhajan Lai and his close relatives.

(c) The report is being processed.

भारत के संविधान के हिन्दी रुपान्तर को वैध मान्यता का प्राप्त होना

545. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के संविधान के हिन्दी रुपान्तर को वैध मान्यता प्रदान नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे कब तक कानूनी मान्यता प्रदान करने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के संविधान के हिन्दी पाठ को तैयार कराए जाने से संबंधित पूरा विषय सरकार के विचाराधीन है ।

अन्तरिक्ष विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति

546. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान नियमानुसार इसकी चार बैठकें नहीं हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीप्रिंटर, टैलेक्स, कम्प्यूटर, इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जैसी यांत्रिक सुविधाएं, जो भाषा के विकास एवं प्रयोग के लिए आवश्यक मानी गयी हैं, प्रदान नहीं की गयी हैं और जिसकी वजह से गत 11 वर्षों से राजभाषा के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पूरे नहीं किये जा सके हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों के लिए जून, 1984 में एक संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया था और इसकी प्रथम बैठक सितम्बर, 1984 में आयोजित की गई थी । आठवीं लोक सभा के गठन के बाद जुलाई, 1985 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया । संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक अक्तूबर, 4, 1985 को आयोजित की गई ।

(ख) और (ग) सभी अन्तरिक्ष केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में हिन्दी टाइप-राइटर प्रदान किए गए हैं । इस विभाग के क्षेत्र "ख" में स्थित अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा कुछ द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिकी टाइपराइटर मंगाए जा रहे हैं, जहां इन्हें उपयोगी और आवश्यक समझा गया है । हिन्दी टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिकी टाइपराइटर जैसी यांत्रिकी सुविधाएं सभी अन्तरिक्ष केन्द्रों में प्रदान नहीं की गई हैं । अधिकांश अन्तरिक्ष केन्द्र/यूनिटें क्षेत्र "ग" (अर्थात् अहिन्दी भाषी क्षेत्र) में स्थित हैं । इस क्षेत्र के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम में इन यांत्रिक सुविधाओं की खरीद के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है । इसके बावजूद विभाग के केन्द्रों/यूनिटों में इन यांत्रिक सुविधाओं के न होने से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में कोई बाधा नहीं आई है, इन यांत्रिक सुविधाओं को चयनात्मक और क्रमिक रूप में अर्जित करने और प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

गृह मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति

547. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी सलाहाकार समिति का गठन नहीं किया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमानुसार इसकी चार बैठकें भी नहीं हुई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भाषा के प्रसार, विकास और प्रयोग को बढ़ाने के लिए टेलीप्रिंटर , टेलेक्स, कम्प्यूटर्स इलैक्ट्रॉनिक टंकण यंत्र आदि जैसी यांत्रिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं जिसके कारण राजभाषा वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पिछले ग्यारह वर्षों में पूरा नहीं किया जा सका है; और